GOVERNMENT OF KARNATAKA

No:RDPR/other/C.Cell/2016

Karnataka Government Secretariat
M.S. Building
Bangalore, Dated:23.03.2017

From,
Principal Secretary to Government
Rural Development and Panchayath Raj Department
M.S Building
Bengaluru.

To,

1. Director
   Abdul Nazir Sab State Institute for
   Rural Development & Panchayath Raj
   Mysuru.
2. Principal
   District training centre's
   All Districts

Dear Sir,

Subject: Regarding e-Panchayat Mission Mode Project Scheme for DBT on-boarding.

Ref: 1. Ministry of Panchayati Raj, GoI. D.O No. N-19011/16/1/2017 e- Palnchayat, Dated:09.03.2017.
2. Chief Secretary, Government of Karnataka Letter No.CS/3623/2017, Dated16.03.2017

*****

As there is a scope of Direct Benefit Transfer (DBT) to be increased. Ministry of Panchayat Raj, GoI has instructed to on board DBT for Mission Mode Project on e-Panchayat. In this regard Ministry of Panchayat Raj, GoI has instructed to include Aadhar as one of the identity documents for receiving e-Panchayat related trainings.

It is observed that SIRD and District Training Institutes (DTI's) are providing trainings to all the elected representatives (ERs) & Govt officials every year.

.....2

Therefore it is instructed to SIRD and all District Training Institutes to capture Aadhar No. or undergo Aadhar authentication of the trainees who are receiving training at your centres. If they (ERs) have not enrolled for Aadhar kindly make necessary arrangements for enrolling them for Aadhar enrollment. It is also instructed that the trainees who have not already enrolled for Aadhar may be enrolled by 30th June 2017.

Yours faithfully,

(K.Yalakkigowda)
Director (e-gov) (i/c) 23/3/17
E/o Joint Secretary to Government
Rural Development & Panchayat Raj Department.

Copy to:

1. PS to Secretary, Ministry of Panchayati Raj, GoI, New Delhi.
2. PS to Chief Secretary, Government of Karnataka, Vidhanasoudha, Bengaluru.
3. PS to Principal Secretary/ Principal Secretary (PR), RDPR, Bengaluru.
4. For Dept. Website.

Dr. SUBHASH C. KHUNTIA
CHIEF SECRETARY
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
GOVERNMENT OF KARNATAKA

320, 3ನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು – 560 001
 # 320, 3rd Floor, Vidhana Soudha
Bengaluru - 560 001
e-mail : cs@karnataka.gov.in
Phone : Off. +91-80-22252442 / 22253716
Fax : +91-80-22258913

No.CS/ 3623 /2017

16.03.2017

I have received your D.O. letter No. N-19011(16)/1/2017-e-Panchayat dated 09.03.2017 regarding e-Panchayat Mission Mode Project Scheme for DBT on-boarding.

In this regard, I have instructed Dr. Nagambika Devi. N., Principal Secretary to Government, Rural Development and Panchayath Raj Department (Phone: 22353929/ Fax: 22353927 email: secyrdpr@gmail.com) to take suitable action and to intimate to your Ministry at the earliest.

ಮು.ಕಾ.ಕಾ(ಸಂ.ರಾ). ಸ್ವೀಕೃತಿ ಸಂಖ್ಯೆ: CS/3623/2017 ದಿನಾಂಕ: 20/3/17

Yours sincerely,

Sd/-
(Subhash C.Khuntia)

Shri Jitendra Shankar Mathur, IAS
Secretary to Government of India
Ministry of Panchayati Raj
Krishi Bhawan
NEW DELHI - 110 001

Copy to: Dr. Nagambika Devi. N., Principal Secretary to Government, Rural Development and Panchayath Raj Department with a copy of the letter from GOI along with its enclosures for information and necessary action. The status may be intimated to this office by 31.03.2017.

16/3/17
(Subhash C.Khuntia)
Chief Secretary

21/3/17

जितेन्द्र शंकर माथुर, आई.ए.एस.
JITENDRA SHANKAR MATHUR, IAS

सत्यमेव जयते

सचिव
भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
कृषि भवन, नई दिल्ली–110001
SECRETARY
Government of India
Ministry of Panchayati Raj
Krishi Bhawan, New Delhi-110001
Tel.: 91-11-23074309, 23389008 Fax: 91-11-23389028
E-mail: secy-mopr@nic.in

D.O. N-19011(16)/1/2017-e-Panchayat

CS/3623/Com/2017

Dated: 9th March, 2017

Dear Shri Khuntia,

As you are aware, the scope of Direct Benefit Transfer (DBT) has now been widened to cover all Central Sector & Centrally Sponsored Schemes, where benefits are being transferred to individual beneficiaries. Mission Mode Project on ePanchayat of the Ministry of Panchayat Raj has been shortlisted for DBT on-boarding.

2. As part of the DBT mandate, Aadhaar has been established as one of the identity documents for receiving e-Panchayat related trainings. In this reference, a Gazette Notification under Section 7 of the Aadhaar Act has now been issued on 17/2/2017 and a copy is attached for your ready reference.

3. Henceforth, an individual eligible to receive training benefit under e-Panchayat is required undergo Aadhaar authentication or provide proof of enrolment for Aadhaar number. As part of this mandate, it is vital that the State/ UT may offer Aadhaar enrolment facilities for the trainees who are not yet enrolled and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the vicinity, the State Government/ UT Administration may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations.

4. In view of above, it is requested to ensure that wide publicity for the requirement of Aadhaar under the e-Panchayat Mission Mode Project scheme. It is also requested that trainees not already enrolled for Aadhaar, may be enrolled by 30th June, 2017 in your State/ UT.

With Best Wishes,

Yours Sincerely,

Encl: As above

(Jitendra Shankar Mathur)

Shri Subhash C. Khuntia,
Chief Secretary
Government of Karnataka
Vidhana Soudha,
Bangalore -560001.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 453] नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 17, 2017/माघ 28, 1938
No. 453] NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17, 2017/MAGHA 28, 1938

पंचायती राज मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

का.आ. 505(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय, पंचायती राज संस्थाओं को आधुनिकता, पारदर्शिता और दक्षता के प्रतीक के रूप में समपरिवर्तित करने के उद्देश्य से ई-पंचायत मिशन पद्धति परियोजना (जिसे इसमें इसके पश्चात् ई-पंचायत कहा गया है) का प्रशासन कर रहा है और इस कार्यक्रम के मूल संघटकों में से एक ई–पंचायत उपयोजनों के संबंध में पंचायत कृत्यकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है;

ई-पंचायत मिशन पद्धति परियोजना के अधीन पूर्वोक्त प्रशिक्षण में भारत की संचित निधि से आवर्ती व्यय किया जाना अंतर्वलित है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा-7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती हैं, अर्थात :-

1. (1) ई-पंचायत के अधीन प्रशिक्षण का फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र किसी व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करे।

   (2) ई-पंचायत के अधीन प्रशिक्षण का फायदा प्राप्त करने के लिए हकदार ऐसे सभी पात्र फायदाग्राहियों से, जिनके पास आधार संख्या नहीं है या जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, किंतु ई–पंचायत के अधीन

प्रशिक्षण का फायदा प्राप्त करने के लिए ईच्छुक हैं, यह अपेक्षित है कि वे तारीख 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करें, परंतु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हों और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाईट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगें।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन का प्रभारी विभाग, जो किसी व्यष्टि से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, से यह अपेक्षित है कि वह ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, आधार नामांकन सुविधाएं प्रस्थापित करे और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील के आस-पास कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, वहां राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई–पंचायत कार्यान्वयन का प्रभारी विभाग, यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेगा:

परंतु उस समय तक जब तक ई-पंचायत के अधीन प्रशिक्षण फायदे के फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किया जाता है, ऐसे व्यष्टियों को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते ई-पंचायत के अधीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ख) (i) नीचे पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (iii) आय-कर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या कार्ड; या (iv) पासपोर्ट; या (v) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (vi) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र शीर्ष पर जारी ऐसे सदस्य का कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित; या (vii) डाक विभाग द्वारा जारी ऐसा पता कार्ड, जिस पर नाम और फोटो हो; या (viii) बैंक फोटो पासबुक; या (ix) किसान फोटो पासबुक; या (x) राशन कार्ड या (xi) एमजीएनआरईजीएस कार्ड; या (xii) किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु यह और कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की जांच, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी।

2. पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ई-पंचायत प्रशिक्षण के फायदाग्राहियों के लिए सुविधाजनक और निर्बाध हकदारियां उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन का प्रभारी विभाग सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:-

(1) राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग द्वारा ग्राम पंचायतों या ब्लॉक पंचायतों आदि के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ई-पंचायत के फायदाग्राहियों को मीडिया के माध्यम से और व्यष्टिक सूचनाएं देकर उनके बीच व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें स्कीम के अधीन आधार की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके और उस दशा में जब उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें निकटतम आधार नामांकन केंद्रो में तारीख 30 जून, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी। स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ई-पंचायत प्रशिक्षण के फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास जैसे कि ब्लॉक या तालुक या तहसील में नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में ई-पंचायत कार्यान्वयन के प्रभारी विभाग से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा पंचायती राज मंत्रालय के अधीन ई-पंचायत प्रशिक्षण के फायदाग्राही, अपने नाम पते, मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उपपैरा (3) के परंतुक में विनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरे देकर, ग्राम पंचायत या ब्लॉक पंचायत या इस प्रयोजन के लिए वैब पोर्टल पर आधार नामांकन हेतु अपने अनुरोध को रजिसटैर कर सकेंगे ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू–कश्मीर राज्यों को छोड़कर उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में प्रभावी होंगी ।

[फा. सं. एन-19011(16)/1/2017-ई-पंचायत]

संजीब कुमार पटजोशी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

NOTIFICATION

New Delhi; the 17th February, 2017

S.O. 505(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Panchayati Raj (hereinafter referred to as MoPR) in the Government of India is administering e-Panchayat Mission Mode Project (hereinafter referred to as e-Panchayat) with an aim to transform the Panchayati Raj Institutions into symbols of modernity, transparency and efficiency, and one of the core components of the programme is to give training to panchayat functionaries on e-Panchayat applications;

And whereas, the aforesaid training under e-Panchayat Mission Mode Project involves recurring expenditure from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of the section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely: –

1. (1) An individual eligible to receive training benefit under e-Panchayat is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.

(2) All such eligible beneficiaries entitled to receive training benefit under e-Panchayat, who do not possess the Aadhaar Number or, not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing training benefit under e-Panchayat, are hereby required to make application for Aadhaar enrolment by 30th June, 2017, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the near vicinity such as Block or Taluka or Tehsil, the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration may provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar:

Provided that, till the Aadhaar is assigned to the beneficiaries of training benefit under e-Panchayat, training under e-Panchayat shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:

(a) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(b)(i) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of Paragraph 2 below; and

(ii) Voter ID card issued by the Election Commission of India; or (iii) Permanent Account Number Card issued by Income Tax Department; or (iv) Passport; or (v) Driving License issued by Licensing authority under Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (vi) Certificate of Identity having photo issued by a Gazetted officer or Tehsildar on an official letter head; or (vii) Address card having Name and Photo issued by Department of Posts; or (viii) Bank Photo Passbook; or (ix) Kisan Photo Passbook; or (x) Ration Card; or (xi) MGNREGS Card, or (xii) any other document as specified by the State Government or Union Territory Administration:

Provided further that the above documents shall be checked by an officer designated by the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle-free training benefit to the beneficiaries under e-Panchayat under MoPR, the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration shall make all the required arrangements including following, namely:-

(1) Wide publicity through media and individual notices through the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration, through Gram Panchayats or Block Panchayats, etc., shall be given to beneficiaries of e-Panchayat under MoPR to make them aware of the requirement of Aadhaar under the scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017 in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(2) In case, beneficiaries of training under e-Panchayat under MoPR are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of Aadhaar enrolment centres in the near vicinity such as the block or taluka or tehsil, the Department in charge of e-Panchayat implementation in the State Government or Union Territory Administration is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations and the beneficiaries of training under e-Panchayat under MoPR may register their request for Aadhaar enrolment by giving their name, address, mobile number and other details specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1 with their Gram Panchayat or Block Panchayat or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. N-19011(16)/1/2017-e-Panchayat]

SANJEEB KUMAR PATJOSHI, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL

Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.02.23 15:22:42 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.